>

Title: Need to streamline mid-day meal scheme in government schools in Hoshiarpur Parliamentary Constituency, Punjab.

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर (पंजाब) के सरकारी स्कूलें, जिनकी संख्या करीब 1800 है, में भारत सरकार द्वारा संचालित मिड–डे–मील स्कीम जो कि गरीब परिवार के छात्र–छात्राओं के लिए शुरू की गयी थी, बंद होने के कगार पर है। छात्र छात्राओं में, अध्यापकों में तथा मिड डे वर्कर्स में पिछले चार–पांच महीनों से चिंता व्याप्त है, क्योंकि विद्यार्थियों को राशन उपलब्ध न होने के कारण खाना नहीं मिल रहा है तथा न ही मिड डे कर्मचारियों को वेतन भत्ता मिल रहा है। पंजाब सरकार ने खाद्यान्न का (केवल जिला होशियारपुर में) 2 करोड़ रूपया आढ़तियों का देना है तथा 1 करोड़ 14 लाख के करीब मिड डे वर्कर्स का बकाया है। भारत सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह मिड डे मील स्कीम शुरू की थी जिसमें भारत सरकार 75 प्रतिशत धनराशि तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत धनराशि का योगदान देती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि राज्य में मिड डे मील स्कीम में अनियमितताओं का पता लगाया जाए तथा होशियारपुर में मिड डे मील स्कीम को तुरन्त पुनः क्रियान्वित किया जाए।